BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

+91 0612 2547371
+91 85442 99526
https:// biharfoundation. bihar.govt.in

सम्प्रति बिहार

बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति

बिहार के महत्वपूर्ण अखबारों में छपे **सकारात्मक** समाचारों का संकलन

आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी सोमवार विक्रम संवत् 2079। 27 जून 2022

JKDESIGN 8369994118

6TH FLOOR, INDIRA BHAWAN, RCS PATH, PATNA-800001. BIHAR, INDIA.

राज्य सरकार ने इंडस्ट्रीयल पार्क के लिए बियाडा को बनाया नोडल एजेंसी, जमीन अधिग्रहण करने की जिम्मेदारी आईडीए को

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गया के डोभी में बनाएगी इंडस्ट्रियल पार्क

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

अमृतसर-हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) पर गया जिला के डोभी प्रखंड में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) यानी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने जा रही है। इसके लिए स्पेशल परपस व्हेकल (एसपीवी) बनाई जा रही है। इस एसपीवी में 50 फीसदी केंद्र और 50 फीसदी राज्य की हिस्सेदारी होगी। राज्य सरकार इसके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि, जिसमें अधिगृहित की जाने वाली भूमि और सरकारी भूमि की कीमत अपनी हिस्सेदारी के रूप में देगी। वहीं, केंद्र सरकार इसके समतुल्य राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में देगी। राज्य सरकार ने आईएमसी के लिए केंद्र से सहयोग और दूसरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बियाडा को नोडल एजेंसी बनाया है। जो एसपीवी के शेयर होल्डिंग और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट में भी सहयोग करेगा। जबकि जमीन अधिग्रहण करने की जिम्मेवारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अॉथिरिटी (आईडीए) को दी गई है। आईएमसी के लिए डोभी में 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है।

सर्वे और डीपीआर पर तेजी से चल रहा है काम

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य तैयार गुड्स को पोर्ट और रॉ मेटेरियल्स को फैक्ट्री तक पहुंचना है। कॉरिडोर को हल्दिया और पारादीप पोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने पर भी काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट निगम की तकनीकी टीम के प्रमुख अजय शर्मा ने बताया कि अभी सर्वे और डीपीआर बनाने का का काम चल रहा है।

योजना क्रियान्वयन के लिए गठित की गई एनआईसीडीआईटी, सीएम सदस्य

अमृतसर-हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह सात राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। इसकी लंबाई 1839 किलोमीटर होगी। केंद्र सरकार की योजना है कि प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य में इसके किनार एक-एक इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर और ड्राइ पोर्ट विकसित किया जाए। केंद्र ने इस योजना की क्रियान्वयन के लिए नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) गठित किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस ट्रस्ट के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बनाया गया है।

जानिए... क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क को क्या फायदा होगा

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ऐसी रेललाइन से है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन के लिए किया जाएगा। इसके लिए देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बिहार होकर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा। इससे एक तरफ जहां कच्चे माल मंगाने में आसानी होगी। वहीं, दूसरी तरफ तैयार वस्तुओं को देश के अलग-अलग स्थानों पर जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे माल ढुलाई की खर्च में कमी आएगी। इसका सीधा फायदा निर्यातकों को मिलेगा। भारतीय उत्पादों की लागत में कमी आएगी और इससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी करने में कामयाब होंगे।

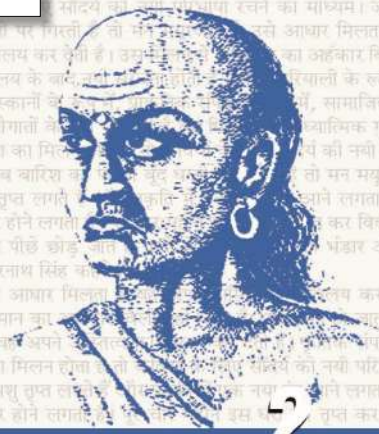

सौजन्य से दैनिक भास्कर | पटना | 27.06.2022 | पृष्ठ सं० 04

शाही लीची व इससे बने उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार

अच्छी खबर

आत्मनिर्भर भारत योजना

- केंद्रीय मंत्रालय ने उद्योग विभाग से मांगी लीची किसान, व्यवसायियों व उद्यमियों की सूची
- केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल है जिले की प्रसिद्ध शाही लीची

12 हजार हेक्टर भूमि पर लीची की पैदावार होती है जिले में

01 लाख टन लीची की पैदावार होती है सालाना मुजफ्फरपुर जिले में

लीची पर बनेगा बेसलाइन डाटा

लीची को निर्यात से जोड़ने के लिए बेस लाइन डाटा तैयार किया जाएगा। जिले में 12 हजार हेक्टर भूमि पर लीची की पैदावार होती है। सालाना एक लाख टन लीची की पैदावार होती है। लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि विदेश में बहुत कम लीची का निर्यात होता है। कुछ कंपनी खाड़ी व यूरोप के देशों में लीची व इससे जुड़े उत्पादों का निर्यात करती है। वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट के तहत लीची को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से योजना शुरू की गई है।

मुजफ्फरपुर, कार्यालय संवाददाता। जिले की पहचान शाही लीची आत्मनिर्भर भारत योजना से विदेश में धूम मचाएगी। केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल शाही लीची व इससे बने उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। लीची व इससे बनने उत्पादों के निर्यात की स्थिति में यहां के स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा। लीची व उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप बनाने के लिए किसानों, व्यवसायियों, उद्यमियों व कारीगरों को तकनीकी मदद दी जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय ने उद्योग विभाग से लीची किसानों, उद्यमियों, कारीगरों व व्यवसायियों की सूची मांगी है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शुरू किए गए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दो साल पहले मुजफ्फरपुर की शाही लीची का चयन किया गया था। योजना में शामिल लीची व इसके उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने के लिए पैकेजिंग, ढुलाई व भंडारण आदि पर किसानों, उद्यमियों, कारीगरों व व्यवसायियों को तकनीक आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी।जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल लीची के लिए उद्योग मंत्रालय व विभाग के स्तर से कार्य चल रहा है। इसके लिए लीची से जुड़े किसानों, उद्यमियों, कारीगरों व व्यवसायियों की सूची मांगी गई है। मुजफ्फरपुर को शाही लीची की राजधानी भी कहा जाता है क्यों कि यहां लीची का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बताया जाता है कि यहां विभिन्न किस्मों की लीचीमें लगभग अस्सी फीसदी हिस्सा शाही लीची का है। इसलिए जब भी मुजफ्फरपुर का नाम आता है तो अनायास ही शाही लीची का नाम आता है। दूसरी बात बगल के जिलों की लीची से इसका स्वाद व सुगंध में काफी अंतर होता है। शाही लीची के फल मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। एक फल का वजन लगभग 20.5 ग्राम होता है। फल का आकार गोल से लेकर हार्ट के आकार में होते हैं।

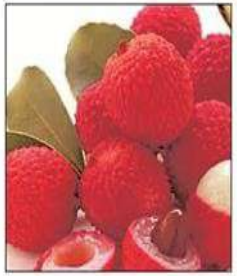

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 27.06.2022 | पृष्ठ सं० 12

BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

राज्य के हर जिले में होना है 75 तालाबों का निर्माण

बिहार में 2852 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। अमृत सरोवर के निर्माण के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में अब-तक कुल 2852 जगह चिह्नित कर लिये गये हैं। इनमें 1050 के निर्माण कार्य शुरू कर दिये गए हैं। शेष में भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। अमृत सरोवर के लिए सरकारी जमीन अथवा जहां पहले से तालाब हैं, उसे ही अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाना है। जो तालाब सूख गये हैं अथवा भर गये हैं, उनका भी इस योजना के अंतर्गत चयन किया गया है। निजी तालाब इसमें नहीं लिये जाएंगे।

ग्रामीण विकास विभाग निरंतर जिलों से अमृत सरोवर की प्रगति रिपोर्ट ले रहा है। मालूम हो कि राज्य के हर जिले में 75-75 तालाबों के निर्माण और इनके जीर्णोद्धार का काम किया जाना है। आजादी के 75 साल के मौके पर मनाये जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत उक्त निर्णय लिये गये हैं। जल के संरक्षण और भू-जल स्तर को और बेहतर करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत तालाबों की खुदाई करने के बाद उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तालाब के चारों ओर पौधरोपण भी किया जाएगा। सालोंभर इसमें पानी रहे, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी।

- 1050 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया
- कटिहार में सबसे अधिक 101 का चयन

मनरेगा के तहत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा

मनरेगा योजना के तहत इन तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जीर्णोद्धार के बाद इन तालाबों में बतख और मछली पालन पर भी आगे निर्णय लिया जाएगा। सबसे अधिक कटिहार जिले में 101 अमृत सरोवर के लिए जगह चिह्नित कर लिये गये हैं। वहीं छोटे जिले शिवहर में 27 तो अरवल में 35 जगह चिह्नित हुए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बड़े जिले में 75 से अधिक अमृत सरोवार विकसित किये जाएंगे। वहीं, जो छोटे जिले हैं, वहां 75 से कम संख्या में भी अमृत सरोवार बनेंगे। हालांकि हर जिले में 75 की संख्या के अनुसार राज्य में 2850 अमृत सरोवर होते हैं। पर, 2850 से अधिक जगह चिह्नित कर लिये गये हैं।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 27.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

मुंगेर-मिर्जाचौकी एनएच-80 फोरलेन ग्रीनफील्ड सड़क 2024 तक होगी पूरी

योजना

संवाददाता ▸ पटना

मुंगेर-मिर्जाचौकी एनएच-80 फोरलेन ग्रीनफील्ड सड़क का करीब 124 किमी लंबाई में करीब 5788 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2024 तक निर्माण पूरा हो जायेगा. इसका निर्माण शुरू करने के लिए निर्माण एजेंसी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है.

फिलहाल सड़क पर ट्रैफिक के आवागमन और उसके भार का आकलन अंतिम चरण में है. इस सड़क के बनने से भागलपुर से होकर पश्चिम बंगाल और झारखंड आना-जाना आसान हो जायेगा. इससे उद्योग, व्यापार और रोजी-रोजगार में बढ़ोतरी होगी. इस सड़क का निर्माण चार पैकेज में किया जा रहा है. चारों का टेंडर हो चुका है. हालांकि, अंतिम पैकेज के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस और जमीन अधिग्रहण बाकी है. इनमें से पहले पैकेज का निर्माण मुंगेर जिला और अन्य तीन पैकेज में सड़कों का निर्माण भागलपुर जिला में होगा. सूत्रों के अनुसार पहले पैकेज में मुंगेर जिले में करीब 1589 करोड़ रुपये की लागत से करीब 26 किमी लंबाई में सड़क बनेगी. इसके बाद दूसरे पैकेज में करीब 1069 करोड़ रुपये की लागत से करीब 29 किमी लंबाई में सड़क बनेगी. तीसरे पैकेज में करीब 1905 करोड़ रुपये की लागत से करीब 32 किमी लंबाई और चौथे पैकेज में करीब 1225 करोड़ रुपये की लागत से करीब 37 किमी लंबाई में सड़क बनेगी.

- सड़क की लंबाई 124 किमी
- लागत 5788 करोड़ रुपये

सौजन्य से प्रभात खबर | पटना | 27.06.2022 | पृष्ठ सं० 10

फसल कैलेंडर से हो बागों की देखभाल : विवेक

आम महोत्सव संपन्न

संवाददाता ▷ पटना

विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि हमारा सारा प्रयास उत्पादन तक ही सीमित है. किसान व कृषि पदाधिकारियों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार आम की तुड़ाई के बाद हम उस बाग के तरफ मुड़ कर भी नहीं देखते हैं. उत्पादन के बाद बगीचों की देखभाल कैसे करनी है. कब क्षत्रक प्रबंधन करना है, कब पौधा संरक्षण के उपाय और कब पौधों के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना है? सभी को यह फसल कैलेंडर तैयार करने की जरूरत है. विवेक कुमार सिंह रविवार को ज्ञान भवन में दो दिवसीय आम महोत्सव-सह-प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किये. कृषि विभाग को सलाह दी है कि मानव संसाधनों का क्रॉप कैलेंडर के हिसाब से बागवानी के गतिविधियों में उपयोग करने से हमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी. मौके पर कृषि सचिव डॉ एन सरवण कुमार ने बताया कि 10 हजार किसान एवं आमजनों ने महोत्सव का भ्रमण किया. मौके पर नंद किशोर, निदेशक उद्यान के अलावा कृषि विभाग के पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, धनंजयपति त्रिपाठी, आभांशु सी जैन आदि मौजूद रहे.

आम महोत्सव-सह-प्रतियोगिता के विजेता को सम्मानित करते विकास आयुक्त.

वैशाली के राजेश बने आम शिरोमणि, 95 अन्य भी पुरस्कृत : कृषि सचिव ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले गोरौल, वैशाली के राजेश कुमार को आम शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गयी. विकास आयुक्त ने उन्हें प्रमाणपत्र व मोमेंटो के साथ 10 हजार रुपये का विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया. प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक शाखा में तीन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृषकों एवं कलाकारों को पुरस्कृत किया गया. 66 लोगों को प्रथम, द्वितीय तथा 29 प्रतिभागियों को तृतीय पुरस्कार दिये गये. प्रथम पुरस्कार में पांच , द्वितीय में चार तथा तृतीय पुरस्कार में तीन हजार रुपये और प्रमाणपत्र दिये गये.

52 सेकंड में दो आम खाकर फर्स्ट आये साहिल : 05-10 साल के बच्चों की आम खायो प्रतियोगिता में साहिल कुमार, पालीगंज ,पटना ने प्रथम, सागर कुमार, फुलवारीशरीफ ने द्वितीय तथा रुद्रचंद्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. तीनों विजेताओं ने 52 से 96 सेकेंड में दो आम खाये. उन्होंने बताया कि आम नक्काशी प्रतियोगिता में रुदचंद्र, पटना सिटी ने प्रथम, निभा कुमारी ने द्वितीय तथा करिश्मा कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया.

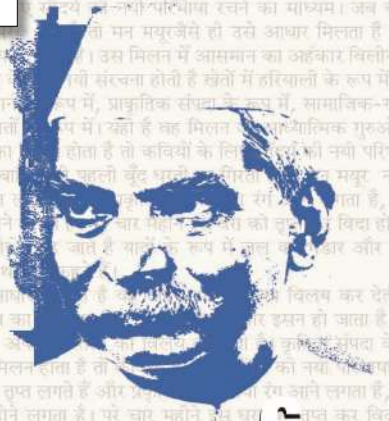

सौजन्य से प्रभात खबर | पटना | 27.06.2022 | पृष्ठ सं० 10

बिहार कोविड अपडेट

⇒ कुल सक्रिय मामलों की संख्या	693
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान नए पॉज़िटिव मामलों की संख्या	142
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या	87
⇒ कुल वैक्सीनेशन	13,53,44,437
⇒ कम से कम एक डोस	7,11,16,601
⇒ पूर्ण वैक्सीनेटेड	6,13,30,969

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

विदेश अवस्थित चैप्टर

- कतर
- दक्षिण कोरिया
- जापान
- हॉग कॉग
- यू.ए.ई.
- सिंगापुर
- बहरीन
- न्यूजीलैंड
- कनाडा
- यू.एस.ए.
- ऑस्ट्रेलिया
- सऊदी अरब

देश अवस्थित चैप्टर

मुम्बई	हैदराबाद	पुणे
चेन्नई	नागपुर	गुजरात
कोलकाता	वाराणसी	गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन के जुड़ने के लिए

बिहार फाउंडेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। वर्तमान मे बिहार फाउंडेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउंडेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें -

https://biharfoundation.bihar.gov.in.